THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; THE MINISTER OF THE STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): Sir, there is an agreement that we don't respond immediately to Zero Hour mentions. I have taken note of the issues raised by the hon. Members. I will bring it to the attention of the Government.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we are taking up Special Mentions, as a special case, because there is still time left. The legislative business will be taken up at 2 o'clock.

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार) : सर, ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : दो बजे से ...**(व्यवधान)**... मंत्री तैयार थे, मगर ...**(व्यवधान)**...

श्री राजनीति प्रसाद : सर, ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप बैठिए न। इसमें विवाद किस बात का है? ...**(व्यवधान)**...

SPECIAL MENTIONS

Demand to resolve the plight of Indians working in Spain

SHRI AVTAR SINGH KARIMPURI (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I want to draw the attention of the House to an issue of public importance concerning the plight of over 5000 Indians, majority of them from Punjab, who are earning their livelihood by working in Spain in the hotel industry, agricultural and piggery farms. But their livelihood is at stake due to the changes made by the Spanish Government in the immigration rules by stipulating that the immigrants have to produce Police Clearance Certificate (PCC) issued by the Union Government of the country of the immigrant for permanent immigration purposes.

But this long pending demand of the immigrants for getting the PCC from the Union Home Ministry in New Delhi was not heeded to and they had to stage a protest *dharna* outside the Indian Consulate in Barcelona on Monday. They have also been compelled to launch a hunger strike in front of Indian Embassy in Madrid.

I request the Union Home Ministry to immediately address the needs of Indians working in Spain by issuing the said Police Clearance Certificate immediately by amending its rules. I also request the Prime Minister's Office (PMO) to intervene in this matter and direct the Indian High Commission in Spain to liaisen with the Spanish Government through diplomatic channel to protect the rights of Indians working there immediately.

सरदार तरलोचन सिंह (हरियाणा) : सर, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूं।

Demand to give fertilizer subsidy to farmers directly

श्री मोती लाल वोरा : उपसभापति महोदय, मेरे विशेष उल्लेख का विषय है - खाद सब्सिडी सीधे किसानों को दिया जाना।

महोदय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा वर्तमान में सब्सिडी का 80 प्रतिशत भाग संबंधित उर्वरक उत्पादन करने वाली कम्पनियों को सीधे दिया जा रहा है और मात्र 20 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों की जांच रिपोर्ट आने के बाद दिया जाता है। दुखद स्थिति यह है कि निजी उर्वरक कम्पनियों द्वारा जाली दावे बनाकर रसायन और उर्वरक मंत्रालय से सब्सिडी ली जा रही है, जबकि वास्तव में उनमें से अधिकांश का अस्तित्व ही नहीं है।

Economic Offence Wing (EOW) द्वारा की गई जांच के समय न तो इन कंपनियों ने अपने उर्वरक उत्पादन संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए और कई स्थानों पर तो तथाकथित कंपनियों का अस्तित्व ही नहीं था। इस प्रकार उर्वरक उत्पादक कम्पनी के नाम पर सरकारी धन की खुलकर लूट की जा रही है। EOW की जांच में यह भी एक खुलासा हुआ है कि जो कुछ उर्वरक की आपूर्ति की भी गई, वह दुपाहिया या तिपाहिया वाहन के द्वारा की गई तथा उसे सरकारी दस्तावेजों में ट्रक दर्शाया गया। EOW के अनुसार प्रतिवर्ष केवल उत्तर प्रदेश में ही 1200 करोड़ का घोटाला है तथा पूरे देश में लगभग 1,20,000 करोड़ का है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उर्वरक कम्पनियों को दी जाने वाली सब्सिडी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, कम्पनियों को अब तक दी गई सब्सिडी की जांच कराई जाए तथा सब्सिडी सीधे किसानों को उपलब्ध कराई जाए।

श्री महेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं अपने आपको श्री वोरा जी के स्पेशल मेंशन के साथ एसोसिएट करता हूं।

Demand to Expedite Completion of National Highway No: 16 by The Border Roads Organisation connecting Chhattisgarh and Andhra Pradesh

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़) : उपसभापति महोदय, मेरे स्पेशल मेंशन का विषय है – सीमा सड़क संगठन छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश को शीघ्र जोड़े।

महोदय, सभी जानते है कि छत्तीसगढ़ व आंध्र सर्वाधिक नक्सल प्रभावित है। छत्तीसगढ़ में बस्तर के केन्द्र जगदलपुर से आंध्र के निजामाबाद तक का राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 16 का काम सीमा-सड़क संगठन को 2001 में दिया गया था। निर्माण कार्य की धीमी गति होने के कारण वह निर्धारित अवधि, यानी 2010 तक पूरा होता नहीं दिखता। क्षेत्र के नक्सल ग्रस्त होने के कारण साधारण ठेकेदार उसे कर भी नहीं सकते। चूंकि सड़क निर्माण क्षेत्र की सुरक्षा व विकास के लिए शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक है, मेरा सरकार से आग्रह है कि वह सीमा सड़क संगठन को न केवल काम पर बनाए रखे वरन् उसके काम में आ रहे अवरोधों को भी दूर करे।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : महोदय, मैं श्री श्रीगोपाल व्यास जी के इस विशेष उल्लेख को एसोसिएट करता हूं।

Demand to take steps to make River Ram Ganga free of pollution

श्री वीर पाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से रामगंगा नदी के प्रदूषण के विषय में कुछ कहना चाहता हूं।

महोदय, रामगंगा नदी उत्तराखंड के कालागढ़ बांध से निकलकर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के शाहजहांपुर होते हुए फर्रुखाबाद जनपद में गंगा नदी में मिल जाती है। उक्त नदी में उक्त जनपदों में रहने वाली जनता की उतनी ही आस्था है, जिस तरह से आम जन की गंगा नदी में आस्था है, वहां दशहरा व पूर्णिमा को